Govt should extend sops to 2015: HCL Insys chief

Shelley Singh
NEW DELHI

THE last few months have been tough for the hardware players, with very few buyers for new products and services. While the market is looking better now, India will have to look at a strong hardware policy that encourages IT manufacturing as it becomes a bigger consumer of technology products and services, says **Ajai Chowdhry, chairman & chief executive of HCL Infosystems**. In an interview with **ET**, Mr Chowdhry discusses the IT agenda of political parties, need for hardware manufacturing, market for computers and related issues.

"If you look at the future, the import of component and hardware is going to be over $300 billion by 2012-2015, with 60-70% imported, and if you don't have manufacturing here, we will have a huge import bill, may be higher than oil!

AJAI CHOWDHRY CHAIRMAN & CEO, HCL INFOSYSTEMS

How do you view the stand taken by political parties on IT?

It's very interesting that all main political parties see IT as a big enabler. If you look at the five years of NDA and five years of UPA, there has been a strong view on IT adoption here. The fact that they are talking about it gives us a very good feeling. In the past five to six years, there has been a solid impetus on domestic IT.

Though an area which needs lot of attention is hardware. Currently, the special incentive package scheme (SIPS) to attract investments for semiconductor chip making is going to be over by 2010. Whichever government comes, should extend it to at least 2015 so that we get something going.

The SIPS policy by default benefited solar PV cells manufacturing.

That was not the objective. It was to get chip making, LCD manufacturing and disk drive manufacturing to India. Proposals came in for semiconductors and for LCD, but no proposal came for disk drive and many proposals came for solar PV cells. We need to ensure a balance: One to two chip makers, one to two LCD makers, one disk drive maker, at least.

If you look at the future, the import of component and hardware is going to be over $300 billion by 2012-2015, with 60-70% imported, and if you don't have manufacturing here, we will have a huge import bill, may be higher than oil!

bits & BYTES

How has the computer market fared in the recent months?

Last couple of quarters have been bad. The situation has been made more difficult due to the severe volatility of the rupee. Production has fallen. Prices went up frequently and that reduced affordability. The biggest issue is that financing is not available to consumers.

But the overall economy has been bad...

The reality is if you make it easy to buy, people will buy more. If you look at last two months, there has been a change in auto industry because of cheaper financing available, but in the PC industry there has been no change due to lack of financing options. Our hardware association has suggested to the government to look at financing options for computers. Proliferation of PC/notebook is essential to create more knowledgeable people out there. The president of Brazil adopted IT as a strategy. Korea adopted a strategy that everybody at home will have high-speed broadband and then the PC/notebook market took off parallel to it. Brazil has taken the view that everybody must have a computer and broadband. To increase penetration of computers and broadband, the push has to come from the top. That has not happened in India.

As far as services are concerned which are the areas that hold promise?

There are quite a few areas like healthcare, education, power and security which look very attractive. In power, the government will spend Rs 50,000 crore under the accelerated power development and reform programme (APDRP). We are one of the selected system integrators for this and have done three projects in Haryana, Rajasthan and Himachal Pradesh. It will take off post elections. Security is another big area and has no connect to slowdown. After the 26/11 Mumbai attacks, interest is very high in this area. It's estimated to be a $1-billion per year spend with both enterprises and government increasing high-tech security outlay. Education is another fast growing area. On the other hand, sectors like retail and banking have been less attractive in the current market.

PC खरीदने के लिए लोगों को फाइनेंस सुविधा मिले

आईटी के उपयोग की सरकारी जागरूकता बढ़ने से सुधरे हालात, लेकिन चुनौतियां कायम

हार्डवेयर कंपनियों के लिए पिछले कुछ दिन काफी चुनौती भरे रहे हैं। मंदी की वजह से नए उत्पाद खरीदने वाले लोगों की संख्या में भारी कमी दर्ज की गई है। अब जब बाजार की स्थिति बेहतर लग रही है, तो भारत को हार्डवेयर उत्पादों के प्रति दमदार नीति बनानी होगी, जिससे आईटी मैन्युफैक्चरिंग को प्रोत्साहन मिल सके। एचसीएल इंफोसिस्टम्स के चेयरमैन और सीईओ **अजय चौधरी** ने **शैली सिंह** को बताया कि राजनीतिक दलों को भारत में हार्डवेयर निर्माण को बढ़ावा देने के लिए उचित कदम उठाना चाहिए

कीमतें बढ़ने के कारण लोगों ने हार्डवेयर पर खर्च कम कर दिया है। इसमें सबसे बड़ा मसला यह है कि उत्पाद खरीदने के लिए फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध नहीं हैं

अजय चौधरी

चेयरमैन एवं सीईओ, एचसीएल इंफोसिस्टम्स

आईटी के मसले पर राजनीतिक दलों के कदम को आप किस तरह देखते हैं?

यह काफी रोचक बात है कि आईटी को भारत में जरूरत की चीज समझा जाता है। अपने-अपने शासनकाल में एनडीए और यूपीए ने आईटी को अपनाने में खासी दिलचस्पी दिखाई है। सच्चाई यह है कि राजनीतिक दल इस मसले पर जितने गंभीर हैं, उससे बहुत अच्छी भावना जग रही है। पिछले पांच-छह सालों में घरेलू क्षेत्र में आईटी के मसले पर काफी काम किया गया है। हार्डवेयर क्षेत्र पर हमें अभी काफी ध्यान देने की जरूरत है। सेमीकंडक्टर चिप बनाने के लिए निवेश को बढ़ावा देने में स्पेशल इंसेंटिव पैकेज स्कीम (एसआईपीएस) का बड़ा योगदान है और यह 2010 में खत्म होने जा रही है। नई सरकार को इसे बढ़ाकर 2015 तक करना चाहिए जिससे हार्डवेयर का विकास जारी रह सके।

एसआईपीएस नीति से सोलर पीवी सेल बनाने वालों को भी फायदा हुआ है?

इस नीति का उद्देश्य यह नहीं था, पर उन्हें फायदा हुआ। यह नीति चिप मैन्युफैक्चरिंग, एलसीडी मैन्युफैक्चरिंग और डिस्क ड्राइव के लिए बनाई गई थी। सेमीकंडक्टर और एलसीडी के लिए तो प्रस्ताव आए, पर डिस्क ड्राइव के लिए कोई प्रस्ताव नहीं आया। सोलर पीवी सेल के लिए भी काफी प्रस्ताव आए। हम वास्तव में इसके लिए एक बैलेंस चाहते हैं, एक-दो चिप निर्माता हों, एक-दो एलसीडी निर्माता और कम से कम एक डिस्क ड्राइव निर्माता जरूर हो। अगर आप भावी योजनाओं को देखें तो 2012-15 तक कंपोनेंट और हार्डवेयर का आयात 300 अरब डॉलर को पार कर जाएगा। यह अनुमान 60-70 फीसदी आयात का है, अगर हम स्थानीय स्तर पर निर्माण शुरू नहीं करेंगे तो आयात की राशि इससे भी अधिक हो सकती है।

कंप्यूटर बाजार की गति कैसी रही है?

पिछली कुछ तिमाही बाजार के लिए ठीक नहीं रही है। रुपए में उतार-चढ़ाव की वजह से मुश्किलें और बढ़ी हैं। उत्पादन में भी कमजोरी दर्ज की गई है। इन वजहों से कीमत बढ़ी और लोगों ने हार्डवेयर पर खर्च कम कर दिया है। इसमें सबसे बड़ा मसला यह है कि उत्पाद खरीदने के लिए फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध नहीं है।

लेकिन इस समय तो अर्थव्यवस्था की ही हालत खराब है....

अगर आप लोगों के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे तो वह सामान खरीदेंगे। अगर आप पिछले दो महीने के आंकड़े देखें तो आपको पता चलेगा कि आसान फाइनेंस की सुविधा से लोग वाहन खरीदने के लिए उत्साहित हुए हैं। पीसी इंडस्ट्री में ऐसे विकल्प नहीं होने की वजह से कोई फर्क नहीं पड़ा है। हमारे हार्डवेयर एसोसिएशन ने सरकार से मांग की है कि कंप्यूटर उत्पाद खरीदने के लिए फाइनेंस सुविधा के विकल्प पर विचार करे। इससे अधिक से अधिक लोगों को कंप्यूटर साक्षर बनाने के लक्ष्य को पूरा करने में मदद मिलेगी।

जहां तक सेवाओं की बात है, कौन सा क्षेत्र आकर्षक लग रहा है?

हेल्थकेयर, शिक्षा, ऊर्जा एवं सुरक्षा सेवाओं के हिसाब से आकर्षक क्षेत्र हैं। ऊर्जा क्षेत्र में सरकार ने एपीडीआरपी के तहत 50,000 करोड़ रुपए के खर्च की योजना बनाई है। हमने राजस्थान, हरियाणा एवं हिमाचल में इसके लिए तीन प्रोजेक्ट किए हैं। चुनाव के बाद इस बारे में और फैसले लिए जाएंगे।